भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1349
11 फरवरी, 2025 को उत्तर के लिए

अनुवांशिक रूप से संवर्धित मछली

+1349. श्री सुधाकर सिंह:

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार ने देश में अनुवांशिक रूप से संवर्धित (जीएम) मछली पालन की अनुमति दी है और यदि हां, तो इस तरह की अनुमति से पहले की गई अनुमोदन प्रक्रिया, पर्यावरणीय जोखिम आकलन और सुरक्षा नवाचारों का ब्यौरा क्या है;
(ख) भारत के जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीएम मछली शुरू करने के संभावित पारिस्थितिकीय और आर्थिक प्रभावों के बारे में पर्यावरणविदों, मछुआरों और वैज्ञानिकों की चिंताओं को दूर करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;
(ग) आजीविका बढ़ाने, जैव विविधता में सुधार करने और जलवायु परिवर्तन का शमन को कम करने में योगदान देने के लिए समुद्री शैवाल खेती सहित सतत जलीय कृषि प्रथाओं के विकास और संवर्धन के लिए सरकार की रणनीति क्या है; और
(घ) समुद्री शैवाल की खेती में निवेश, पहल और परिणामों के आंकड़े क्या हैं और इसके उत्पादन को बढ़ाने और इसे व्यापक नीली अर्थव्यवस्था के ढांचे में एकीकृत करने के लिए राज्य-वार क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क): मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने देश में कोई आनुवंशिक रूप से संवर्धित / जेनिटेकेली मोडीफाईड (जीएम) मछली की अनुमति नहीं दी है।

(ख): प्रश्न नहीं उठता।

(ग): मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार समुद्री शैवाल की खेती सहित मात्स्यिकी और जलीय कृषि के विकास के लिए प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई), फिशरीज़ एंड एक्वाकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट फंड (एफआईडीएफ), प्रधान मंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना (पीएम-एमकेएसएसवाई) और किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) जैसी विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रही है। पीएमएमएसवाई के अंतर्गत, सतत जलीय कृषि (सस्टेनेबल एक्वाकल्चर) को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न गतिविधियां शुरू की गई हैं जैसे (i) व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण प्रजातियों का आनुवंशिक सुधार कार्यक्रम, गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन के लिए ब्रूड बैंकों, ब्रूड स्टॉक मल्टीप्लीकेशन सेन्टर्स (बीएमसी), हैचरियों और सीड रियरिंग इकाइयों की स्थापना, (ii) स्वदेशी प्रजातियों को बढ़ावा देकर विभिन्न प्रजातियों का प्रसार (iii) गुणवत्तापूर्ण मत्स्य आहार के निर्माण के लिए फीड मिलों की स्थापना, (iv) आइस प्लांट्स, कोल्ड स्टोरेज, फिश मारकेट्स, फिश कियोस्क, इंसुलेटेड फिश वाहन स्थापित करके कोल्ड चेन और मारकेटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, और (v) मात्स्यिकी और जलीय कृषि क्षेत्र में कुशल मैनपावर के लिए क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम।

(घ): पीएमएमएसवाई के अंतर्गत, मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने 98.97 करोड़ रुपए के केंद्रीय अंश के साथ 194.09 करोड़ रुपए की लागत वाली समुद्री शैवाल परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिसमें 47,245 राफ्ट, 65,480 मोनोलाइन/ट्यूबनेट की स्थापना, बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क (मल्टीपरपस सी वीड पार्क) की स्थापना, सी वीड सीड बैंक, समुद्री शैवाल खेती पर पूर्व-व्यवहार्यता मूल्यांकन अध्ययन परियोजनाएं, विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के लिए लाभार्थियों को प्रदान की गई सहायता शामिल है। मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने पीएमएमएसवाई के अंतर्गत तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में समुद्री शैवाल की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न गतिविधियाँ शुरू की हैं जैसे (i) तमिलनाडु में, 75.16 करोड़ रुपए के केंद्रीय अंश के साथ 127.71 करोड़ रुपए की कुल परियोजना लागत से एक बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क की स्थापना जिसका उद्देश्य समुद्री शैवाल किसानों को उच्च गुणवत्ता वाली प्लांटिंग सामग्री की आपूर्ति करना, नए उत्पाद विकसित करने के लिए उत्पाद नवाचार प्रयोगशाला, पानी और समुद्री शैवाल उत्पादों की गुणवत्ता परीक्षण के लिए परीक्षण सुविधा, साथ ही उद्यमियों और प्रसंस्करणकर्ताओं के लिए सिंगल विंडो सपोर्ट उपलब्ध कराना है, (ii) किसानों को गुणवत्ता वाली प्लांटिंग सामग्री की आपूर्ति के लिए समुद्री शैवाल ब्रूड बैंक की स्थापना, (iii) लक्षद्वीप द्वीपसमूह में सी वीड क्लस्टर की स्थापना, जिसमें सीड बैंक, कल्टीवेशन यूनिट्स, प्रोसेसिंग और मारकेटिंग सहित सी वीड वैल्यू चैन का विकास शामिल है, (iv) विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लाभार्थियों को सी वीड कल्टीवेशन के लिए 63.53 करोड़ रुपए की लागत से राफ्ट की 47,245 इकाइयों और मोनोलाइन/ट्यूबनेट विधि की 65,480 इकाइयों को मंजूरी दी गई है । पीएमएमएसवाई के अंतर्गत स्वीकृत इनपुट सहित राफ्ट और मोनोलाइन/ट्यूबनेट का राज्यवार विवरण अनुबंध-I में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, विभिन्न आईसीएआर और सीएसआईआर संस्थानों के लिए 465.07 लाख रुपए की कुल लागत वाली 6 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसमें मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार द्वारा 100% वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ये परियोजनाएँ मुख्य रूप से समुद्री शैवाल की खेती के पूर्व-व्यवहार्यता आकलन अध्ययन, मन्नार की खाड़ी में पारिस्थितिक सुरक्षा उपाय, महाराष्ट्र तट पर सी वीड कल्टीवेशन की शुरुआत, कच्छ की खाड़ी में सी वीड कल्टीवेशन की व्यवहार्यता आकलन और संवर्धन, गुजरात में कोरी क्रीक और उसके आसपास सी वीड कल्टीवेशन के लिए कौशल, क्षमता निर्माण और पूर्व-व्यवहार्यता, तमिलनाडु तट पर कप्पाफाइकस अल्वारेज़ी की व्यापक कल्टीवेशन को बढ़ावा देने के लिए सीड प्लांट उत्पादन पर परियोजना और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश में व्यावसायिक रूप से मूल्यवान सी वीड की पायलट स्केल फ़ार्मिंग की स्थापना पर एक अन्य परियोजना से संबंधित हैं। पीएमएमएसवाई के अंतर्गत सी वीड पर विभिन्न संस्थानों और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को स्वीकृत केंद्रीय क्षेत्र (सीएस) परियोजनाओं का विवरण अनुबंध-II में दिया गया है।

राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एनएफडीबी) ने मछुआरों, मत्स्य किसानों और राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के सरकारी अधिकारियों के लिए सी वीड कल्टीवेशन पर विभिन्न एक्स्पोशर और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इसके अलावा, सीएसआईआर-सीएसएमसीआरआई ने 2017-2025 के दौरान सी वीड कल्टीवेशन और प्रोसेसिंग टेक्नोलोजी पर आयोजित कुल 63 प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 2529 हितधारकों (मछुआरों, उद्योग और उद्यमी) को प्रशिक्षित किया है। इसके अलावा, आईसीएआर-सीएमएफआरआई ने विगत 3 वर्षों (2022-2024) के दौरान सी वीड कल्टीवेशन को बढ़ावा देने के लिए 7490 लाभार्थियों को शामिल करते हुए 102 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं।

****

अनुबंध-I

अनुवांशिक रूप से संवर्धित मछली के संबंध में 11 फरवरी, 2025 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1349 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण:

पीएमएमएसवाई के तहत सी वीड कल्टीवेशन के लिए राज्यवार स्वीकृत राफ्ट और मोनोलाइन/ट्यूबनेट विधि ।

(i) सी वीड कल्टीवेशन के लिए इनपुट सहित राफ्ट

(रुपए लाख में)

क्र. सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	इकाई	लागत
1	आंध्र प्रदेश	26000	390.00
2	कर्नाटक	10000	150.00
3	लक्षद्वीप	500	9.00
4	महाराष्ट्र	1000	15.00
5	तमिलनाडु	9745	146.18
	कुल	**47,245**	**710.18**

(ii) **इनपुट सहित सी वीड कल्टीवेशन के लिए मोनोलाइन/ट्यूबनेट**

(रुपए लाख में)

क्र. सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	इकाई	लागत
1	आंध्र प्रदेश	41200	3296
2	कर्नाटक	400	32
3	लक्षद्वीप	21000	1680
4	महाराष्ट्र	250	125
5	तमिलनाडु	2630	210.4
	कुल	**65,480**	**5343.4**

(रुपए लाख में)

तमिलनाडु में बहुउद्देशीय सी वीड पार्क की स्थापना						
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	**वित्तीय वर्ष**	**कुल परियोजना लागत**	**केन्द्रीय अंश**	**राज्य अंश**	**लाभार्थी अंश**	**अनुमानित लाभार्थी**
तमिल नाडु	2022-23	12771	7516	4894	360	700

अनुबंध II

अनुवांशिक रूप से संवर्धित मछली के संबंध में 11 फरवरी, 2025 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1349 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण:

पीएमएमएसवाई के अंतर्गत सी वीड कल्टीवेशन पर विभिन्न संस्थानों और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को स्वीकृत केंद्रीय क्षेत्र (सीएस) परियोजनाओं का विवरण

क्र.सं.	कार्यान्वयन एजेंसी / परियोजना प्रस्तावक	परियोजना का नाम	परियोजना लागत (रुपए लाख में)
(i)	(ii)	(iii)	(v)
1	सीएसआईआर-केंद्रीय नमक एवं समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान(सीएसएमसीआरआई)	तमिलनाडु तट पर कप्पाफाइकस अल्वारेज़ी की व्यापक खेती को बढ़ावा देने के लिए बीज संयंत्र उत्पादन	53.185
2	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का केंद्र शासित प्रदेश	अंडमान तट पर व्यावसायिक रूप से मूल्यवान समुद्री शैवाल की प्रायोगिक पैमाने पर खेती की पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययन और स्थापना	82.74
3	(i). एनसीएससीएम,एमओईएफएंडसीसी, भारत सरकार (ii). सीएसआईआर-सीएसएमसीआरआई (iii). आईसीएआर-सीएमएफआरआई	तमिलनाडु के मन्नार की खाड़ी में समुद्री शैवाल की खेती की संभावना और पारिस्थितिक सुरक्षा उपायों पर संयुक्त अध्ययन	59.70
4	सीएसआईआर-केंद्रीय नमक एवं समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान (सीएसएमसीआरआई)	महाराष्ट्र के तट पर समुद्री शैवाल की खेती शुरू करने की रणनीतियाँ	121.31
5	आईसीएआर - केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान (सीएमएफआरआई)	गुजरात के कच्छ तट पर कोरी, पडाला और अन्य चयनित स्थानों पर समुद्री शैवाल की खेती की व्यवहार्यता का आकलन और प्रचार गतिविधियों का अन्वेषण	94.92
6	सीएसआईआर-केंद्रीय नमक एवं समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान (सीएसएमसीआरआई)	गुजरात के कच्छ की खाड़ी में कोरी क्रीक और उसके आसपास समुद्री शैवाल की खेती का कौशल, क्षमता निर्माण और पूर्व-व्यवहार्यता आकलन	53.22
		कुल	**465.07**